साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 270 | जौनपुर, गुरूवार, 27 जून 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

सहारा स्टेट में दो अरब की जमीन से हटाया कब्जा

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट कॉलोनी के अंदर पड़ी 11 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाकर नगर निगम ने उस पर अपना बोर्ड लगा दिया है। इस दौरान निगम की टीम को हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा। यह जमीन करीब 20 साल से लावारिस हालत में पड़ी थी। इस पर कॉलोनी के लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्माण भी कर लिए थे। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब दो अरब रुपये है। नगर निगम के नायब तहसीलदार संजय सिंह ने बताया कि जानकीपुरम में सहारा स्टेट को विनिमय में जमीन दी गई थी। इसमें सहारा ने अपनी जमीन तो बेच दी, लेकिन नगर निगम की जमीन भी उसके परिसर में थी। वहां तक जाने का अलग से कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में कॉलोनीवालों ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। किसी ने गैराज बना लिया था तो कोई कुत्ता पाल रहा था। कई लोगों सब्जी उगा रहे थे। सभी कब्जों को हटा दिया गया। यह जमीन बहुत कीमती है। यहां जमीन का रेट पांच हजार रुपये वर्गफीट चल रहा है। तहसील की टीम के साथ संयुक्त रूप से जांच करने के बाद नगर निगम का बोर्ड भी मौके पर लगाया गया है।

थाने के अंदर दरोगा ने खुद को पिस्टल से उड़ाया

बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी जिले के कोठी थाना के अंदर दिनदहाड़े एक युवा दरोगा ने पिस्टल से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार मृतक माइग्रेन नामक बीमारी से पीड़ित था। मौके पर पहुंचे एसपी दिनेश कुमार सिंह पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार कानपुर जिले के मूल निवासी अरुण यादव (26) कोठी थाने में दरोगा के पद पर तैनात थे। अरुण यहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी करते थे। बुधवार की शाम देर तक वह कमरे से नहीं निकले तो अन्य पुलिसकर्मी देखने पहुंचे। खिड़की से झांकने पर अंदर उनका शव दिखाई पड़ा। यह पता चलते ही कोठी थाने में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर एसपी दिनेश कुमार सिंह समेत सभी पुलिस अधिकारी आनन फानन मौके पर पहुंच गए। कानपुर में रह रहे परिजनों को सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई जो घटनास्थल की पड़ताल कर रही है। बताते हैं कि मृतक अविवाहित था। गोली कनपटी में लगी है जो चीरते हुए दूसरी ओर निकल गई। सीओ हैदरगढ़ हर्षित चौहान ने बताया कि सुसाइड नोट में माइग्रेन नामक बीमारी का उल्लेख किया गया है। जांच की जा रही है।

पीएम ने आपातकाल के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला के भाषण की सराहना की

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष घोषित होने के बाद अपने पहले भाषण में, भाजपा के ओम बिरला ने पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का उल्लेख करते हुए आपातकाल के दौरान काले दिनों और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने सदस्यों से आपातकाल के काले दिनों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दो मिनट के मौन के लिए खड़े होने को भी कहा। इसे स्वीकार नहीं किया गया और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और सदन को स्थगित कर दिया गया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने तानाशाही बंद

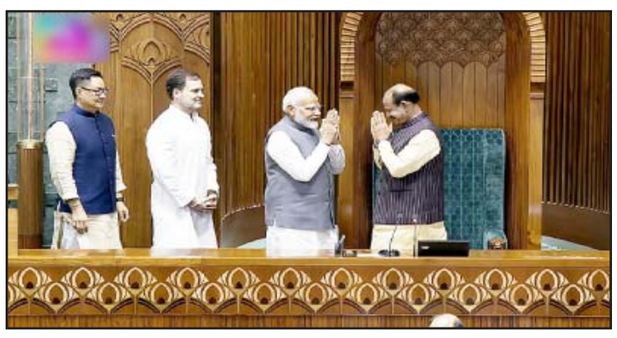

करो जैसे नारे लगाए। हालाँकि, बिरला के भाषण को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा मिली। एक्स को संबोधित करते हुए, पीएम ने लिखा, "मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया उसका भी उल्लेख किया। उन दिनों के दौरान पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था।

उन्होंने आगे लिखा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यह इस बात का एक उपयुक्त उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनता की राय दबा दी जाती है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है।

'पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' पाली थाना पुलिस ने कस्बे के मोहल्ला बिरहाना निवासी एक युवक को नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है।पुलिस ने शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज करके उसे न्यायालय में पेश किया। युवक की तमंचे के साथ फोटो वायरल हुई थी।पाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि कस्बा चौकी इंचार्ज शिव शंकर मिश्रा, कांस्टेबल राकेश प्रताप व दिलीप कुमार ने असमधा रोड से रामनगर को जाने वाले कच्चे मार्ग पर एक युवक को पकड़ा, जामा तलाशी में उसके पास से एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ, पूछताछ में युवक ने अपना नाम अभिषेक पुत्र सुभाष चंद्र निवासी मोहल्ला बिरहाना कस्बा पाली बताया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी की तमंचे के साथ फोटो

सोसल मीडिया पर वायरल हुई थी, आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार हुए अभिषेक का क्राइम रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है जिससे इस अपराधी पर कठोर कार्यवाही की जा सके वही मोहल्ले वासियों का कहना है कि यह व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो चुका है इस पर पुलिस को कड़ी कार्य वाही करनी चाहिए जिससे आम जनमानत को राहत मिल सके।

केंद्र ने दिल्ली सरकार के साथ किया भेदभाव, आतिशी से मिलने के बाद बोले अखिलेश यादव

नई दिल्ली, एजेंसी। एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से मिलने के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा

सत्ता में आई है तब से मुख्यमंत्रियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली में पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद आतिशी को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एलएनजेपी के डॉक्टरों ने कहा कि आतिशी की हालत स्थिर है और उन्हें आईसीयू से वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। यादव ने कहा कि मैं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आया था। वह न केवल बहादुर हैं बल्कि लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं। वह दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार लड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया है। केजरीवाल ने सरकार बनाई और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया, लेकिन केंद्र बाधाएं पैदा कर रहा है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो उन लोगों को विभिन्न मामलों में फंसा रही है जो भाजपा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को पता होगा कि वह बाहर आएंगे।

म्यांमार के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। म्यामांर में भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रहीं हैं। ऐसे में वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत भी चिंतित है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के अपने समकक्ष यू थान श्वे के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत ने म्यांमार में भारतीय सीमा के पास जारी हिंसा पर चिंता व्यक्त की। एस जयशंकर ने म्यामांर के विदेश मंत्री से म्यावाडे शहर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने में सहयोग करने की भी मांग की।

भारत–म्यांमार सीमा के पास बढ़ती हिंसा पर जताई चिंता

भारत के विदेश मंत्री ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की गए एक पोस्ट में लिखा गया है कि बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार में चल रही भारत की परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। जयशंकर ने खासतौर पर भारत–म्यांमार सीमा के पास लगातार

हो रही हिंसा पर चिंता जताई। बता दें कि म्यांमार के कई क्षेत्रों में सेना (जुंटा) और विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। म्यांमार में विद्रोहियों ने पहले से ही कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया हुआ है। अप्रैल के महीने में विद्रोहियों ने जुंटा के सैन्य अड्डे और म्यावाडी स्थित कमान केंद्र पर कब्जा कर लिया था।

'सभी पक्षों से बात करने को तैयार भारत'

बैठक में जयशंकर ने म्यांमार के समकक्ष से कहा कि भारत, म्यामांर में हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा 'म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में भारत–म्यांमार सीमा के पास बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई गई। भारत इस मामले में सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। म्यांमार में चल रही भारत की परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। साथ ही वहां फंसे भारतीय लोगों की स्वदेश वापसी में मदद प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

1 फरवरी, 2021 को म्यांमार में तख्तापलट हुआ था और सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

उपग्रह प्रक्षेपण बाजार के लिए घरेलू मांग काफी नहीं, निवेशकों को राजी करना बड़ी चुनौती - एस. सोमनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख एस सोमनाथ ने बुधवार को कहा कि भारत में उपग्रह प्रक्षेपण बाजार (सेटेलाइट लॉन्च मार्केट) के लिए घरेलू मांग काफी नहीं है। उपग्रह प्रौद्योगिकी (सैटेलाइट टेक्नोलॉजी) के एप्लिकेशन पर और काम करके यह मांग पैदा की जा सकती है। सोमनाथ इंडिया स्पेस कांग्रेस–2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में आना चाहती हैं लेकिन वे ऑर्डर पाने की समयसीमा को लेकर चिंतित हैं। सोमनाथ ने कहा, जब मैं उन कंपनियों से बात करता हूं जो यहां आना चाहते हैं और सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं, तो वे सभी ऐसा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वे पूछते हैं कि ऑर्डर कहां हैं, ताकि वे सुरक्षित रूप से इसमें निवेश कर सकें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कहा,

बड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए निवेशकों को राजी करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, हमें और अधिक घरेलू मांग पैदा करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग पर्याप्त नहीं है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मांग उपभोक्ता और संचार खंड से आएगी, जिसमें निश्चित तौर पर बड़े उपग्रह निर्माता शामिल हैं। हम ऑर्बिटल स्लॉट और फ्रीक्वेंसी को ढूंढना चाहते हैं, जिन्हें सैटेलाइट और लॉन्चर बनाने के लिए उद्योगों को दिया जा सकता है।

यह आंतरिक मांग पैदा करने की दिशा में पहला कदम है। इनस्पेस ने पहले ही एक नया पृथ्वी अवलोकन समूह बनाने के लिए फंडिंग की घोषणा की है। यह घरेलू मांग पैदा करने की दिशा में एक और कदम है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष तक पहुंचने की लागक वैश्विक स्तर पर काफी कम हो गई है, खासतौर पर स्पेसएक्स के कारण। लेकिन भारत की रॉकेट लागत में उस तरह की कटौती की गई है। लागत कम करने से छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण को बढ़ावा मिल सरकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में नए प्रतिभागियों को आकर्षित किया जा सकता है।

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री की 'कठपुतली' की तरह काम कर रहे हैं – जयराम ठाकुर

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पर निशाना साधा और कहा कि वह मुख्यमंत्री की ''कठपुतली'' की तरह काम कर रहे हैं। ठाकुर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास नौ भाजपा विधायकों को अयोग्य ठहराने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने केवल ''सरकार के खिलाफ नारे लगाए।'' ठाकुर ने इस साल मार्च में भाजपा के नौ विधायकों को नोटिस जारी करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। बजट सत्र के दौरान कुछ भाजपा सदस्यों ने कथित तौर पर आसन का अनादर किया था और सदन में कागज फाड़ दिए थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था। ठाकुर ने पठानिया

पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि विधानसभा अध्यक्ष को कुछ पद देने का वादा किया गया है। भाजपा नेता ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार केवल सत्ता बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर भी उनकी (सुक्खू की) पत्नी को आगामी विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया। ठाकुर ने कहा, ''मैं खुद मुख्यमंत्री रह चुका हूं, ऐसा फैसला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना संभव नहीं होता, खासकर कांग्रेस पार्टी में।

मुझे विश्वास है कि बिरला हमें बोलने की अनुमति देंगे – राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। तीन बार के भाजपा सांसद ओम बिरला मंगलवार को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश को एक दुर्लभ मुकाबले में ध्वनि मत से हराया। ओम बिरला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते समय मुस्कुरा रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। उन्होंने ओम बिरला को कुर्सी तक पहुंचाया। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर राहुल गांधी ने कहा, श्मुझे विश्वास है कि आप हमें बोलने देंगे तीन बार के भाजपा सांसद ओम बिरला मंगलवार को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश को एक मुकाबले में ध्वनि मत से हराया।

नये अध्यक्ष को उनके आसन तक पहुंचाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे के साथ संक्षिप्त मित्रता भी साझा की और दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया तथा ओम बिरला का स्वागत किया। ओम बिरला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते समय मुस्कुरा रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी ओम बिरला को कुर्सी तक ले गए। नए अध्यक्ष को कुर्सी तक ले जाने से पहले प्रधान मंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक–दूसरे के साथ थोड़ी देर की दोस्ती भी की।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में लंबित मामलों पर जताई चिंता, लोगों से की लोक अदालत का लाभ लेने की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 29 जुलाई से छह दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगाने की

घोषणा करते हुए कहा कि बेहिसाब लंबित मामलों को लेकर वह बहुत चिंतित हैं।

सीबीआई ने नागरिकों और वकीलों से की ये अपील

उन्होंने देश के नागरिकों और वकीलों से इन परिस्थितियों का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विवाह और संपत्ति पर समझौते से जुड़े मामले, सड़क दुर्घटना के दावों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, सेवा व श्रम से जुड़े मामलों के द्रुत गति से निस्तारण पर लोक अदालत में काम होगा।

कब से लगेगी विशेष लोक अदालत?

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि आगामी 29 जुलाई से तीन अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत चलेगी। सर्वोच्च अदालत पिछले 75 सालों से समय–समय पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसी गतिविधियां चलाती रही है। लंबित मामलों के ढेर देखते हुए इस न्यायिक संस्था के सभी जज इस लोक अदालत के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे।

नागिरकों को मिलता है संतोषजनक न्याय

उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक बहुत ही अनौपचारिक और तकनीक आधारित विधि से मामलों का समाधान करती है।

जनगणना का काम तुरंत करें शुरू – सीएम स्टालिन

तमिलनाडु, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वह जनगणना का काम तुरंत शुरू करे, साथ ही इस बार जाति आधारित जनसंख्या जनगणना भी करे। प्रस्ताव आदेश में उल्लेख किया गया है कि सदन का मानना घ्छै कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार में समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए जाति आधारित जनसंख्या जनगणना आवश्यक है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह जनगणना कार्य तुरंत शुरू करे (जो वर्ष 2021 से होने वाला है) साथ ही इस बार जाति आधारित जनसंख्या जनगणना भी की जाए। इससे पहले दिन में तमिलनाडु के विपक्ष के नेता (एलओपी) एडप्पादी पलानीस्वामी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के कई विधायकों को पूरे विधानसभा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव के बाद किया गया। यह निलंबन तब हुआ जब एआईएडीएमके विधायकों ने कल्लाकुरिची शराब त्रासदी को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस्तीफे की मांग की।

संपादकीय

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना

वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुँचने से रोकने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य और संघीय सरकारों की ओर से द्विदलीय प्रयास चल रहे हैं। राजनेता इस बात की आशंका जता रहे हैं कि नाबालिग ऑनलाइन हानिकारक या अनुचित सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। प्रस्तावित सुधार के साथ–साथ संघीय सरकार की योजना आयु आश्वासन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने की है। आयु सत्यापन के लिए प्रस्तावित उपकरण पहचान पत्र अपलोड करने से लेकर बायोमेट्रिक फेस–स्कैनिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग तक हैं। इनमें से अधिकांश विधियाँ गोपनीयता जोखिम सहित समस्याओं से भरी हुई हैं। विदेशों से किए गए शोध ने पहले ही सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने के संभावित नुकसान के बारे में चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलियाई शोध ने यह भी बताया है कि सूचना तक पहुँचने और समाज में भाग लेने के युवाओं के मौलिक अधिकार के लिए सोशल मीडिया कितना आवश्यक है। ।कअमतजपेमउमदज हालाँकि, इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि प्रतिबंध का समुदाय के सबसे हाशिए पर पड़े युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमने सांस्कृतिक रूप से विविध युवाओं (13–18 वर्ष की आयु) और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में शिक्षकों और नीति निर्माताओं के साथ शोध किया है। हमारे आगामी अध्ययन में हमने पाया कि युवा लोग जो ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर चुके हैं – या जिनके माता–पिता या दादा–दादी ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए हैं – वे सोशल मीडिया के सक्षम उपयोगकर्ता हैं। वे संस्कृति और समुदाय से जुड़ने, अपनी चिंता के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने और डिजिटल क्पहपजंस और अन्य सामाजिक नुकसानों को संबोधित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया प्रतिबंध के बारे में बहस को प्रतिबिंबित करते हुए, हमारे शोध ने यह भी खुलासा किया कि वयस्कों और सांस्कृतिक रूप से विविध युवाओं के बीच डिजिटल और सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर एक अंतर है जो युवा लोगों के जीवन में निभाता है। सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण कैसे बनाया जाए, इस पर भी मतभेद है। युवा लोग क्या सोचते हैं? हमारे शोध में, शिक्षकों और नीति निर्माताओं ने सोचा कि कुछ समुदायों के युवा अनुचित सामग्री तक पहुँचने से संबंधित सामाजिक नुकसानों से अधिक जोखिम में हैं। इसलिए, इन वयस्कों ने सोशल मीडिया के उपयोग पर अधिक अभिभावकीय नियंत्रण और सीमाओं के लिए तर्क दिया। इस बीच, हमारे अध्ययन में युवा लोगों ने दावा किया कि सोशल मीडिया उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा से परे जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है। इनमें शामिल हैंरू परिवार और दोस्तों से जुड़ना, स्थानीय और विदेशी स्तर पर अपनी और अन्य संस्कृतियों के बारे में सीखना, और दुनिया और उसके भीतर अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अपने दैनिक जीवन में अनुभव की जाने वाली प्रणालीगत घृणा और नस्लवाद को संबोधित करने के लिए सक्रियता और वकालत में शामिल होना, डिजिटल समुदायों और प्रशंसकों में भागीदारी और संयम के माध्यम से विषाक्त ऑनलाइन संस्कृतियों को शांत करना। जैसा कि एक प्रतिभागी ने हमें बतायारू युवा लोगों के रूप में, हम महसूस करते हैं, ओह, हमारे पास भी विश्वास और सामान हैं, हमें उन्हें साझा करने की आवश्यकता है .., क्योंकि जाहिर है वयस्क, वे मतदान के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अन्य लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में युवा लोगों के विशेषाधिकार के बारे में बात की, जो सामाजिक मुद्दों पर बोलने और सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए है। उन्होंने इसकी तुलना उन देशों से की, जहाँ सोशल मीडिया सहित मीडिया को राज्य द्वारा सेंसर या प्रतिबंधित किया जाता है। यह भी एक बिंदु है जो इस आयु वर्ग के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कुछ खतरों की ओर इशारा करता हैरू मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए जागरूकता बढ़ाना और चीजों के बारे में विरोध करना महत्वपूर्ण है ख्३, क्योंकि वे एक स्वतंत्र देश हैं और उनके पास जानकारी का उपयोग करने की पहुँच है ख्३, मुझे लगता है कि अगर आपके पास वह पहुँच होती, तो आपको ख्३, उन लोगों के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए जिनके पास ऐसा अवसर नहीं है। सोशल मीडिया पर हमेशा सार्वजनिक और मुखर होने के बजाय, युवा लोगों ने शांत, कम सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लिया। ये जानकारी खोजने और संयम और सम्मानजनक संवाद के माध्यम से सहायक समुदायों का निर्माण करने पर केंद्रित थे। एक प्रतिभागी ने कहारू डिस्कॉर्ड ख्व्यक्तिगत समुदायों के साथ ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, में एक निश्चित व्यक्ति था जिसे मैं नियंत्रित करता हूँ, जिसे मैंने और मेरे दोस्तों ने बनाया था, जो यह जरूरी नहीं था कि वह डिस्कॉर्ड पर कुछ कर रहा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह कुछ बहुत ही असभ्य चीजें कर रहा था। इसलिए हमने उसे काट दिया और उसे डिस्कॉर्ड और ग्रुप चौट और इस तरह की चीजों से प्रतिबंधित कर दिया। बाद वाला बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान बहस में, राजनेता युवा लोगों की सुरक्षा को राजनीतिक, कानूनी और मंच हस्तक्षेप पर निर्भर मानते हैं। यह सांस्कृतिक रूप से विविध युवा लोगों की एजेंसी को नकारता है। यह उनकी क्षमताओं और सोशल मीडिया के कुशल नेविगेशन को भी अनदेखा करता है। हमारे अध्ययन में, युवा लोगों ने सामूहिक नुकसान के खिलाफ अपनी आवाज उठाने और विषाक्त ऑनलाइन संस्कृतियों को शांत करने के लिए उपकरण और कौशल सीखने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया तक उनकी पहुँच पर प्रतिबंध लगाने से, ये कौशल बन जाते हैं।

अब आसान नहीं रह गया देश पर इमरजेंसी थोपना

जयसिंह

भारत में अंतिम बार आपातकाल की घोषणा हुए 49 साल गुजर गए मगर उस दौर की ज्यादतियों की यादें आज भी राजनीतिक क्षेत्रों में गूंजती रहती हैं। खासकर प्रेस की स्वतंत्रता के हनन के लिए वह दौर एक चिरजीवी उदाहरण बन गया। 25 जून 1975 से लेकर 21मार्च 1977 तक चले इतिहास के उस काले दौर से भी पहले देश में युद्धों के दौरान आपातकाल की घोषणाएं हो चुकीं थीं जो कि वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपरिहार्य थीं जिनको लेकर देशवासियों को काई ऐतराज नहीं हुआ। लेकिन जून 1975 के आपातकाल की घोषणा से सारा देश इतना विचलित हुआ कि न केवल तत्कालीन सत्ताधारी दल को अपितु तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी जनता ने हरा कर सबक सिखा दिया।

अब इतिहास की बात हो गई इमरजेंसी

भारत में, आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर चिंता का विषय रहा है। विशेष रूप से 1975–1977 में घोषित आपातकाल की अवधि के दौरान देशवासियों ने असहनीय उत्पीड़न झेले। लेकिन आज की तारीख में कोई शासक या प्रधानमंत्री चाहकर भी 1975 वाला आपातकाल देश पर लागू नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के 44वें संशोधन के बाद आपातकाल लागू करने के प्रावधान वाला अनुच्छेद 352 तो मौजूद है मगर उसके तहत 1975 का जैसा आपातकाल लागू करना लगभग नामुमकिन ही है। अब तो अनुच्छेद 356 का बेजा इस्तेमाल भी संभव नहीं है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट को इन परिस्थितियों की समीक्षा करने का पूरा अधिकार हो गया है। संविधान संशोधन–44 और न्यायिक समीक्षा के साथ ही जनजागरूकता के चलते अब असाधारण युद्धकालीन या संशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अलावा आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। असाधारण आर्थिक संकट में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सका। यह स्थिति आपातकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है।

संविधान के 44 वें संशोधन ने लगाया इमरजेंसी पर ब्रेक

दरअसल, सत्तर के दशक में जब देश आपातकाल की ज्यादतियों और नागरिक अधिकारों के हनन से कराह रहा था तो 1977 के आम चुनाव में उन्हीं ज्यादतियों के गर्भ से जनता पार्टी के शासन के रूप में एक ऐसे जनादेश का जन्म हुआ जिसकी पहली प्राथमिकता आपातकाल की ज्यादतियों की संभावनाओं को सदा के लिये समाप्त करने की थी। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में अपने घोषणापत्र में भी 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाप्त कर आपातकाल लागू होने से पहले की संविधान की स्थिति बहाल करने का वायदा करने के साथ ही ऐसी नई व्यवस्था की बात कही थी जिससे दुबारा कोई आपातकाल के नाम पर नागरिक अधिकारों का हनन न कर सके। यह संविधान संशोधन विधेयक तत्कालीन कानून मंत्री शांति भूषण द्वारा 16 दिसम्बर 1977 को लोकसभा में पेश किया गया था जिसमें संविधान के 30 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव था। इसमें 42वें संशोधन के प्रस्तावों को हटाने के प्रस्ताव भी थे। चूंकि संविधान संशोधन में राज्यसभा की स्वीकृति और आधे से अधिक राज्यों की राय भी जरूरी थी इसलिए राज्यसभा द्वारा पारित कराए गए संशोधनों के साथ इसे 7 दिसम्बर 1978 को लोकसभा में पारित कराया जा सका और आधे से अधिक राज्यों से रैटिफिकेशन के बाद इसको तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी की स्वीकृति 30 अप्रैल 1979 को मिल सकी। 25 जून 1975 को जब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय के अधिकांश मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को इसकी जानकारी नहीं थी। जबकि इतना बड़ा फैसला कैबिनेट की सहमति से लिया जाना था और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह पर आपातकाल की स्वीकृति देनी थी। चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को विचलन का असाधारण अधिकार प्राप्त है इसलिये उस समय इंदिरा गांधी ने भी बिचलन से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी थी। बिचलन के तहत लिए गए फैसले की औपचारिक जानकारी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा बाद में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को दी जा सकती है। इसी विचलन के अधिकार का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने स्वतः ही निर्णय लेकर राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सलाह दे दी थी। देश में पहली बार बिचलन के अधिकार का प्रयोग इतने बड़े फैसले के लिए किया गया था। यह बिचलन का अधिकार आज भी है मगर आपातकाल लागू करने के मामले में इस अधिकार को बहुत सीमित कर दिया गया है। संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को अब आपातकाल लागू करने की मामले में सिफारिश को दुबारा विचार के लिए कैबिनेट का लौटाने का अधिकार मिल गया है जबकि पहले यह अधिकार नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री अब मनमानी नहीं कर सकते। दरअसल, जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 को मुख्य रूप से आपातकाल की ज्यादतियों के जवाब में लागू किया गया था। इसने संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की घोषणा जारी करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह लेना अनिवार्य कर दिया। अब घोषणा को एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसने राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को छह महीने तक सीमित कर दिया, जब तक कि संसद द्वारा इसे बढ़ाया न जाए। इसने सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में है।

विश्व समुदाय को ठोस कदम उठाने की जरूरत

कुलदीप

अफगानिस्तान में तालिबान को तीसरा साल हो गया है। 15 अगस्त, 2021 को उन्होंने दूसरी बार सत्ता पर कब्जा किया था। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं के प्रति उनके रवैये में तब्दीली आएगी। उनको शिक्षा पाने की इजाजत भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत समेत ऐसे बहुत से देश हैं, जो महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी है,ध्जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान में महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं। हाल ही में तालिबान द्वारा 14 महिलाओं और 60 से ज्यादा लोगों को दंड के तौर पर सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारे गए, जिसकी सारी दुनिया में निंदा हो रही है। उल्लेखनीय है कि तालिबान के 1990 के दशक के शासन में भी यही होता था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर ने कहा कि नवंबर, 2022 से अप्रैल, 2023 के बीच अफगानिस्तान में ऐसी शारीरिक सजा के 41 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 58 महिलाएं और 274 मर्द और बच्चों को अलग–अलग अपराधों के लिए कोड़े मारे गए। नाबालिग और कमसिन बच्चियों को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियों में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ रही है। तालिबान ने सत्ता संभालते वक्त वादा किया था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन वे घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकतीं और न ही नौकरी कर सकती हैं। अफगानी महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। तालिबान ने अफगानी महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विश्वास दिलाया था, लेकिन वहां हो कुछ और ही रहा है। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश ऐसे शासन की मदद नहीं करना चाहते, जिसने लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा रखी है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वूमेन ने बताया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। उसने वहां महिलाओं का दमन रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। और कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की हालात में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने आवश्यक हैं। तालिबान ने तीन वर्षों के शासन में सुधार का कोई कदम नहीं उठाया। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा करके 70 से ज्यादा ऐसे आधिकारिक फरमान जारी किए हैं। और वे अभी तक कायम हैं, जिसका महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस समय 11 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा रहीं और एक लाख से ज्यादा महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। महिलाएं निर्णय लेने का अधिकार हासिल करना चाहती हैं। वे न केवल अपने घरों में, बल्कि सरकार व अन्य स्थानों पर भी अधिकार चाहती हैं, लेकिन उनकी ये मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए उनका दर्जा व परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में 190 देशों का सर्वे किया है। इसमें अफगानिस्तान में महिलाओं को करीब 90 फीसदी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, मुक्ति आंदोलन इत्यादि शामिल हैं। आईएसआईएस सैलानियों पर हमले कर रहा है। इसमें महिलाएं ही ज्यादा प्रभावित होती हैं। चंद दिनों पहले ही आईएसआईएस ने ऐसे हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगानिस्तान में बराबर हजारा बिरादरी शिया नागरिकों पर जुल्म ढा रही है। जब भी शिया बिरादरी के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता है। पिछले बीस साल

में भारत ने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा विकास कार्य किया है। वह अब भी उसे मानवीय सहायता देने की कोशिश करता रहा है। भारत चाहता है कि अलग–अलग देशों की ओर से दी जा रही मदद का दुरुपयोग न हो और अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बने। इसलिए जरूरी है कि अफगानिस्तान सबसे पहले अपनी जनता का भरोसा जीते। वह जब अपनी आवाम का भरोसा हासिल कर लेगा, तब उसका बदला हुआ रवैया सामने आ सकेगा। फिलहाल कोई भी देश उसे मान्यता नहीं दे रहा है। वहां महिलाओं को जो कोड़ों की सजा दी जा रही है, उसे तुरंत बंद करना होगा और शिक्षा के दरवाजे खोलने होंगे। अफगानिस्तानी/महिलाओं के सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

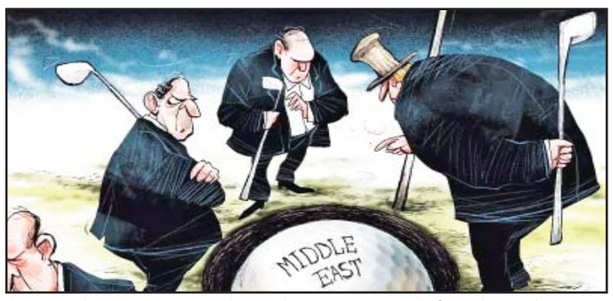

अस्तित्व के जंगल में सभी अकेले

आदित्य

इस हफ्ते की शुरुआत में मेरी एक अंशकालिक सहयोगी ने एक युवक की कहानी सुनाई, जिसकी मात्र दस रुपये के लिए कई लोगों की मौजूदगी में बेरहमी से हत्या कर

दी गई। हुआ यों कि वह युवक गोलगप्पे का ठेला लगाता था, वहीं उससे कुछ कदम की दूरी पर एक सब्जी बेचने वाला था, जिसने इससे दस रुपये का एक प्लेट गोलगप्पा उधार लिया था। बाद में उसने पैसे देने से इन्कार कर दिया, तो दोनों के बीच इस बात पर कहा–सुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने एक बोतल उठाकर गोलगप्पे वाले का गला काट दिया। यह अपराध जितना चौंकाने वाला है, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि यह घटना एक व्यस्त और चहल–पहल भरे बाजार में लोगों की नजरों के सामने हुई। मेरी घरेलू सहायिका ने बताया कि लोग सिर्फ देख रहे थे और घटना का वीडियो बना रहे थे। कोई भी न तो उसे बचाने आया और न ही बीच–बचाव करने आया। इसका नतीजा यह हुआ कि दो मासूम बच्चों के बीस वर्षीय पिता ने खून से लथपथ जमीन पर गिरकर दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य से यह सार्वजनिक उदासीनता का अकेला मामला नहीं है, बल्कि देश भर के कई शहरों और कस्बों में ऐसा होता है। पिछले हफ्ते न्यूज चौनलों पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सुबह–सुबह एक युवती को एक ऐसे व्यक्ति ने मार डाला, जिसे उसका पूर्व प्रेमी बताया जा रहा था। यह मामला प्रेम प्रसंग में आई कड़वाहट का लग रहा था। पीठ पर बैग लटकाए हुए उस लड़के ने युवती पर लगातार हमला किया, जबकि वहां खड़े अन्य लोग, खासकर उससे काफी बड़े लोग यह सब देख रहे थे। यह कोई ऐसा मामला नहीं था, जिसमें कोई खतरनाक अपराधी बंदूक या किसी घातक हथियार से लोगों को डरा रहा हो, बल्कि यह एक छोटे कद का लड़का था, जो युवती पर हमला कर रहा था। ऐसी हिंसा के सामने लोगों की यह निष्क्रियता क्या बताती है? पिछले वर्ष एक अन्य लड़के को पत्थर से एक लड़की के सिर को कुचलते हुए देखा गया था, जबकि आसपास खड़े कई लोग मूकदर्शक बने हुए थे। शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे इन भयावह घटनाओं को कैद करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वे यह भी दिखाते हैं कि लोगों की नैतिकता कितनी गिर चुकी है। इन सभी मामलों में और अन्य मामलों में भी तथ्य यह है कि असहाय और असुरक्षित पीड़ित को क्रूरता का सामना करना पड़ता है और लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

यह हमें न केवल हैरान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक बार घर से निकलने के बाद आप बिल्कुल अकेले होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी उदाहरण हैं, जब भले लोगों ने मामले में हस्तक्षेप किया और उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ साल पहले मुंबई में रुबेन और कीनन नामक दो लड़कों को तब अपनी जान गंवानी पड़ी, जब वे अपने समूह की दो लड़कियों को छेड़खानी करने वालों से बचा रहे थे। उस समय भी काफी सारे लोग अपराधियों को उन्हें पीटते और चाकू घोंपते देख रहे थे, लेकिन किसी ने बीच–बचाव नहीं किया। कीनन तो वहीं मर गया, लेकिन रुबेन 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ता रहा। एक बार फिर यह घटना राष्ट्रीय समाचार बनी। ऐसी घटनाओं पर बाद में आक्रोश जताना और नैतिक रूप से निंदा करना एक नियमित अभ्यास हो गया है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं बदलता है। कीनन और रुबेन की घटना 2011 में हुई थी और अब 2024 में भी हम इन स्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये घटनाएं बहुत दूर नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में हो रही हैं, जैसा कि मेरी घरेलू सहायिका ने बताया। बहुत संभव है कि हममें से कोई भी ऐसी किसी घटना में फंस जाए और बहुत कम मदद मिले।

पश्चिम एशिया में एक नया महान खेल चल रहा

आदित्य

भू–राजनीति में, ग्रेट गेम एक ऐसे क्षेत्र में संभावित प्रतियोगिता के निर्माण का संदर्भ है, जहां दो या अधिक प्रभावशाली शक्तियों के बीच हितों का टकराव अपरिहार्य प्रतीत होता है। इस शब्द का पहली बार अकादमिक रूप से प्रोफेसर एच डब्ल्यू सी डेविस ने 1926 में इस्तेमाल किया था। यह मध्य एशिया में 19वीं सदी की एंग्लो–रूसी प्रतिद्वंद्विता को संदर्भित करता है। यह केवल टकराव नहीं था, बल्कि रूस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों द्वारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न उप–क्षेत्रों में प्रभाव के क्षेत्रों को स्थापित करने की रणनीति थी, जो बाद में किसी भी ग्रेट गेम की रणनीति की एक स्थापित विशेषता बन गई। पश्चिम एशिया इसी तरह की ग्रेट गेम रणनीतियों के लिए प्रवण और आदर्श रूप से अनुकूल है। अमेरिका और रूस ने शीत युद्ध के दौरान कड़ी पैरवी की। अमेरिका ने हमेशा इजरायल का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश ऊर्जा उत्पादक अरब देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। अमेरिका के लिए, पश्चिम एशिया की स्थिरता और इसे संघर्ष–मुक्त रखना ऊर्जा हितों की अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता थी। भूतपूर्व सोवियत संघ ने मुख्य रूप से मिस्र और सीरिया के उग्रवादी अरब राज्यों का समर्थन किया ताकि वे उसके हित के क्षेत्र में बने रहें और अमेरिका के पक्ष में किसी भी रणनीतिक असंतुलन को रोकें। सोवियत संघ और अमेरिका वअपमज न्दपवद ंदक ।उमतपबं दोनों ही अपने घरेलू तटों से बहुत दूर थे, लेकिन उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर था। अमेरिका ने सैन्य अड्डे स्थापित करने का विकल्प चुना, विशेष रूप से समुद्री स्थानों पर, और विभिन्न सुविधाओं पर संपत्ति और सैनिकों को पार्क किया, इस प्रकार कुछ राजशाही को आकस्मिक सुरक्षा भी प्रदान की। रूस ने इसका सहारा नहीं लियाय हालाँकि, उनके लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए दांव बहुत अधिक थे कि वे काले सागर के बाहर गर्म पानी में पैर जमा सकें। रूसियों ने 2015 में सीरिया में अपने हितों, विशेष रूप से सैन्य सुविधाओं को बरकरार रखने और लुटेरे दाएश के खतरे से बचने के लिए वापस आ गए, जो उस समय पूरे पश्चिम एशिया को धमकी दे रहा था। पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों का एक पुराना विवाद हमेशा हाइड्रोकार्बन के इर्द–गिर्द घूमता था। जैसे–जैसे शेल गैस के भंडारों की खोज होती गई, अमेरिका ने इस क्षेत्र में तुलनात्मक रणनीतिक रुचि खो दी और इंडो–पैसिफिक को प्राथमिकता देने लगा, जो 2015 के बाद दुनिया भर में रणनीतिक हितों का आकर्षक 'गो–टू' क्षेत्र बन गया। यह इतनी जोरदार वापसी क्यों कर रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के समय में? ट्रंप प्रशासन अपनी इस कथित धारणा में गलत नहीं था कि पश्चिम एशिया हमेशा दुनिया का रणनीतिक केंद्र बना रहेगा, भले ही कई शांगरी ला वार्ताएं हुई हों। जरा देखिए, कैसे? अधिकांश व्यापार मार्ग इस क्षेत्र में मिलते हैंय स्वेज नहर इस क्षेत्र की एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है। ऊर्जा के लिहाज से, यह अभी भी केंद्रीय क्षेत्र बना हुआ है, जो दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्रों जापान और चीन के अलावा आबादी वाले और तेजी से उभरते भारत को ऊर्जा प्रदान करता है। यहां संघर्षों ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का एक तरीका निकाला है कि बाकी दुनिया स्पिन–ऑफ में शामिल हो जाए। पिछले 75 वर्षों के बेहतर हिस्से के लिए, संघर्ष के वैचारिक चालक यहीं से निकले हैं। राजनीतिक इस्लाम का जन्म यहीं हुआ और दुनिया भर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अस्थिरता में इसके योगदान को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। हाल के दिनों में, संघर्ष–ग्रस्त क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पलायन मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से हुआ है, जिसके कारण यूरोप के स्थिर समाजों में सामाजिक अशांति आई है। एक घटना जो अभी तक पश्चिम एशिया को प्रभावित नहीं कर पाई है, वह है खुले परमाणुकरण की राजनीतिय गुप्त भाग कुछ समय से व्याप्त है। यही कारण है कि उपरोक्त बोर्ड और साथ ही साथ सुलगते संघर्षों में ऐसी घटनाओं को ट्रिगर करने की क्षमता है जो बेकाबू हो सकती हैं और बहुत कुछ पैदा कर सकती हैं। कई उप–क्षेत्रों में ईरान की सामान्य छद्म युद्ध रणनीति, सीरिया का गृह युद्ध, यमन में हौथियों के खिलाफ सऊदी अरब का युद्ध और अब गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ उग्र इजरायली युद्ध, सभी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें वापस खींचने के लिए बड़ी शक्तियों के प्रभाव की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि अमेरिका, जिसके पश्चिम एशिया में स्थिरता और अशांति नहीं होने के अपने सभी हित हैं, गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को भी नरमी से आगे बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया केवल अमेरिका के लिए शिकारगाह नहीं है, हालांकि उसने यहां पर्याप्त सैनिक और अन्य सैन्य संपत्तियां तैनात करके अपने हितों को बनाए रखा है, जिससे वह दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में जा सकता है और निर्माण कर सकता है। चीन अब इस क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए है, जैसा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए उसकी बहुचर्चित मध्यस्थता से स्पष्ट है, लेकिन संयोग से वर्तमान रणनीतिक हलकों में इस पर बहुत चर्चा नहीं होती है। पश्चिम एशियाई महाखेल में अपनी भूमिका के बारे में चीन की अवधारणा क्या होगी? चीन के यहां कोई सैन्य संपत्ति तैनात करने की संभावना नहीं है। इस क्षेत्र के कोई भी देश इस मोड़ पर अपनी धरती पर विदेशी सैनिकों को नहीं देखना चाहेंगे। अमेरिका की मौजूदगी जारी है क्योंकि यह शीत युद्ध की याद दिलाती है, जब रणनीतिक माहौल काफी अलग था। चीन अपने ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं पर प्रभाव बनाए रखने और वहां निरंतरता बनाए रखने के लिए कठोर शक्ति के अलावा हर तरह का साधन अपनाएगा। वह किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल होने से परहेज करेगा।

दहेज के खिलाफ जंग में आपका साथ है जरुरी - जिला प्रोबेशन अधिकारी

हम सबको मिलकर दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना है

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना) जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुई हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। हम सबको मिलकर दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि दहेज, शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओ की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानूनी (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। उन्होंने बताया है कि इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अपराध है, बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। उन्होंने बताया कि दहेज से सम्बन्धित किसी भी शिकायत जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024017 वन स्टॉप सेन्टर अथवा 181 महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर या वन स्टॉप सेन्टर, निकट सीएमओ ऑफिस परिसर, हरदोई में सम्पर्क कर सकते हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों की मुख्य विकास अधिकारी में लिया समीक्षा बैठक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मॉदड़ के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, कायाकल्प, मिशन प्रेरणा फेस–2, निपुण भारत के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालय का एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण कर शिक्षकों तथा छात्रों की उपस्थिति की जांच करें। अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करें। ईट–भट्ठों, बस अड्डा, स्टेशन आदि सहित अन्य स्थनों पर जाकर बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करते हुए उनका नामांकन कराये। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों को मीटिंग के माध्यम से और गांव में डुग्गी और मुनादी करके नामांकन बढाएं। अध्यापगण एसएमसी और पीटीएम बैठक कर पिछले सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों तथा उनके अभिभावकों को सम्मानित करें। निपुण के लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रीत करें। बैठक के दौरान उन्होंने मूकबधिर एवं दृष्टि बाधित बच्चों के लिए दिव्यांग जन कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा बचपन डे–केयर स्कूल संचालित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रधान के माध्यम से ऐसे दिव्यांग बच्चों की चिन्हाकन किए जाने हेतु निर्देशित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. गोरखनाथ पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी आर0बी0 सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थूराम, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी दिव्या शुक्ला, डायट प्राचार्य, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

यूपी-112 का द्वितीय चरण.... मुख्यमंत्री ने झंडी दिखा नए उच्चीकृत पीआरवी को किया रवाना

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने वाली यूपी–112 के द्वितीय चरण में शामिल नए उच्चीकृत पीआरवी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखा कर रवाना किया. इस मौके पर मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना की गरिमामयी उपस्थिति रही।

24 एजेंसियों से हुआ है एकीकरण

यूपी–112 के द्वितीय चरण में नई तकनीक के साथ संसाधनों को भी बढ़ाया गया है, ताकि जनमानस को पारदर्शी तरीके से त्वरित पुलिस सहायता प्रदान की जा सके. नागरिकों की मदद का दायरा बढ़ाने के लिए यूपी–112 ने द्वितीय चरण में 15 नई एजेंसियों के साथ एकीकरण किया है. जबकि पहले चरण में 9 एजेंसियों के साथ 112 का एकीकरण था. इस तरह अब 24 एजेंसियों के साथ 112 का एकीकरण हुआ है।

कॉल टेकर्स और पीआरवी की संख्या बढ़ी

दूसरे चरण में कॉल टेकर्स की संख्या बढ़ा कर 825 की गयी है जबकि पहले चरण में कॉल टेकर्स की क्षमता 673 थी, कॉल टेकर्स बढ़ने से अब प्रतिदिन औसतन 28,000 कालर्स की आपात सहायता की जा रही है, जबकि पहले सहायता का ये आंकड़ा 18,500 का था. इसी तरह दूसरे चरण में पीआरवी की संख्या को बढ़ा कर 6278 किया गया है, जबकि पहले चरण में यह

संख्या 4800 थी. कॉल टेकर्स की संख्या बढ़ने से जहाँ आपात सेवा लेने वालों की संख्या बढ़ी है वहीं पीआरवी की संख्या बढ़ने से पीड़ित तक जल्द पुलिस सहायता पहुँच रही है. नागरिकों को पीआरवी ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

तकनीक का हुआ भरपूर प्रयोग

दूसरे चरण में यूपी–112 ने तकनीक का भरपूर प्रयोग किया है. ताकि नागरिकों को पारदर्शी तरीके से त्वरित पुलिस सहायता मिल सके, कॉलर की सटीक लोकेशन पता करने के लिए 112 मैप तकनीक का उपयोग कर रहा है. यूपी पुलिस इस सेवा को प्रयोग करने वाला पहला भारतीय पुलिस संगठन है. पीआरवी पर तैनात कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरे दिए गए हैं जिससे पुलिस कर्मी घटना स्थल की फोटो और वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं.

PTZ कैमरों से रखी जाएगी नजर

पीआरवी पर PTZ कैमरे लगाये गए हैं. इससे संवेदनशील घटनाओं की रियल टाइम मोनिटरिंग जिला मुख्यालयों और यूपी–112 द्वारा किये जाने की व्यवस्था है. कैमरों से पारदर्शिता व अपराधों के इन्वेस्टीगेशन में मदद मिलेगी।

जौनपुर इमरती पर विशेष डाक आवरण से होगी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार–प्रसार– पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। डाक विभाग द्वारा 'वित्तीय समावेशन डाक मेला' एवं जीआई उत्पाद पर 'विशेष आवरण व विरूपण' विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हिंदी भवन, में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त जौनपुर जिले के प्रथम जी.आई. उत्पाद 'जौनपुर इमरती' पर विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन किया। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र की लाभार्थियों को पासबुक वितरित करते हुए सशक्त नारी–समृद्ध समाज का आह्वान किया। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि अपनी ऐतिहासिक विरासतों के साथ जौनपुर खान पान के मामले में भी समृद्ध रहा है। जौनपुर की इमरती का इतिहास ब्रिटिश शासन काल (लगभग 200 वर्ष) का है। इसकी देश–विदेश में अत्याधिक मांग है। इसकी भौगोलिक विशिष्टता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 30 मार्च, 2024 को इसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यह दर्जा प्राप्त करने वाला यह जौनपुर का प्रथम उत्पाद है। इस पर विशेष आवरण से इसकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार–प्रसार होगा। यह 'वोकल फॉर लोकल' की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को भी आगे बढ़ाता है। भारत की समृद्ध विरासत को डाक टिकटों और विशेष आवरण के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक संचारित करने में डाक विभाग की अहम भूमिका है। श्री यादव ने बताया कि वाराणसी क्षेत्र के आसपास के 34 उत्पादों को जीआई प्राप्त है। दुनिया के किसी भी भूभाग में यह सर्वाधिक है। इन जीआई उत्पादों से लगभग पच्चीस हजार करोड़ का सालाना कारोबार और 20 लाख लोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लाभान्वित हैं। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने इस अवसर पर 'वित्तीय समावेशन महामेलाश में सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र तथा डाक जीवन बीमा के लाभार्थियों को पासबुक व पॉलिसी बॉन्ड भी प्रदान किए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाककर्मियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई भी की। बेटियों को श्सुकन्या समृद्धि योजनाश की पासबुक वितरित करते हुए कहा कि इसके माध्यम से बेटियाँ आत्मनिर्भर बनेंगी तो श्आत्मनिर्भर भारतश की संकल्पना भी साकार होगी। डिजिटल इण्डिया और वित्तीय समावेशन की संकल्पना से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने हेतु डाक घर आज चलते–फिरते बैंक की भूमिका निभा रहे हैं। डाकघरों में एक ही छत के नीचे तमाम सेवाओं को उपलब्ध कराकर और भी कस्टमर फ्रेंडली बनाया गया है। अधीक्षक डाकघर परमानंद कुमार ने बताया कि जौनपुर इमरती पर जारी उक्त विशेष आवरण मय विरूपण 25 रुपए में जौनपुर प्रधान डाकघर एवं फिलैटिलिक ब्यूरो, प्रधान डाकघर वाराणसी में उपलब्ध होगा। इस अवसर पर अधीक्षक डाकघर परमानंद कुमार, आइपीपीबी सीनियर मैनेजर साक्षी सिन्हा, सहायक डाक अधीक्षक विपिन यादव, निरीक्षक डाक बलबीर सिंह, व्यास मुनि पाठक, दिलीप पांडेय, पोस्टमास्टर विष्णु देव मिश्रा सहित तमाम अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित रहे। जौनपुर इमरती साधारण इमरती से बिल्कुल अलग होती है। इसे विशेष रूप से हल्की आंच पर पकाया जाता है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में देशी चीनी (खांडसारी), देशी घी और उड़द की दालें शामिल हैं। यह इतनी मुलायम होती है कि मुंह में डालते ही घुल जाती है।

पीयू परिसर के पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 3-4 जुलाई को

प्रवेश पत्र 25 जून से हो रहा है डाउनलोड

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने परिसर में चलने वाले पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पीयूकैट) सत्र 2024–25 तीन और चार जुलाई को होगी।

पीयू कैट के समन्वयक प्रोफेसर मिथिलेश सिंह ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश परीक्षा डी फार्मा, बीटेक, बीए एलएलबी, बीबीए, बीएससी, बीकाम ऑनर्स, बीसीए, एमसीए, एमबीए तथा एमबीए के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा 3 और 4 जुलाई को होगी। इन परीक्षाओं का एडमिट कार्ड 25 जून से डाउनलोड हो रहा है। प्रवेश परीक्षा तीन चरणों में होगी प्रथम चरण 9 से 11, दूसरा चरण 12 से 2, तीसरा चरण तीन से पांच बजे होगी। सभी परीक्षाएं परिसर के उमानाथ सिंह इंजीनियरिंग संस्थान में होगी, जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही है उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश मेरिट के आधार पर 5 जुलाई से लिया जाएगा। अभ्यर्थी संबंधित विभाग से संपर्क कर प्रवेश ले सकते हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट अइेचन.ब.पद पर उपलब्ध है। विदित हो कि विश्वविद्यालय परिसर में बीएससी, बीए, बीकाम, बीए एलएलबी आनर्स (फाइव इयर इनटीग्रेटेड कोर्स), बीए (जनसंचार, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र), बीसीए, बीबीए, बीटेक, एमएससी, एमए, एमबीए, एमसीए, एमए जनसंचार, एमटेक, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मेकनिकल इंजीनियरिंग, पीजी डिप्लोमा इन जेंडर वूमेन स्टडी, ट्रासलेशन के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के 39वें वार्षिक महाधिवेशन सम्पन्न हुआ

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के 39वें वार्षिक महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डॉ० आशीष कुमार गोयल ने यह कहा कि मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरुप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी के साथ चर्चा कर शीघ्र ही वापस ली जाएंगी। इसके पूर्व अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से जोरदार ढंग से यह मांग रखी थी कि मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरुप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा 19 मार्च 2023 को की गई घोषणा के अनुसार वापस ली जाएं। महाधिवेशन में बिजली अभियंताओं ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश की जनता को 24घण्टे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने हेतु संकल्पबद्ध रहने की शपथ खड़े होकर सामूहिक तौर पर ली। महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने अपने प्रतिवेदन में पूर्व में हुए समझौते के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू करने, इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने,प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन भत्ता लागू किए जाने, सस्ती बिजली उत्पादन हेतु ओबरा डी व अनपरा–ई समेत अधिक से अधिक परियोजनाएं उत्पादन निगम के पूर्ण स्वामित्व में लगाने व ऊर्जा निगमों में भी प्रदेश के अन्य विभागों की भांति मार्च 2005 तक नियुक्त सभी अभियन्ताओं को पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की। महाधिवेशन में महासभा द्वारा यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि यदि मार्च 2023 के आंदोलन के दौरान की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती है तो महासभा ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव को अधिकृत किया है कि उत्पीड़नात्मक

कार्यवाहियां समाप्त करने हेतु यथोचित निर्णय लिए जाएं और महासभा इस संबंध में उनके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का पूर्ण समर्थन करेगी और तदनुसार प्रदेश के समस्त विद्युत अभियंता कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष राजीव सिंह ने उच्च प्रबंधन स्तर पर विभागीय अभियंताओं की तैनाती किए जाने एवं सेवा शर्तों में हुए परिवर्तन को वापस लेने के साथ अन्य मुद्दों को उठाया। महाधिवेशन में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एस एस निरंजन, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने अनुभव साझा किए व मार्गदर्शन दिया। महाधिवेशन के कार्यक्रम का संचालन अभियंता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाधिवेशन विशेषांक 2024 का विमोचन भी मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया गया एवं महाधिवेशन में अभियंताओं द्वारा पूर्व में स्थापित किए गए कीर्तिमान व प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने व उपभोक्ता सेवा को और बेहतर किये जाने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में एक शार्ट फिल्म के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के कीर्तिमानों एवं अभियन्ताओं के कार्यों को सराहा गया।

महाधिवेशन में विशेष अतिथि के रूप में विभिन्न श्रम संघोंध्सेवा संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी डॉ सचिन वैश्य,डॉ अमित सिंह, महेंद्र राय ,पी के दीक्षित,डी के मिश्रा,सरजू त्रिवेदी,सोहैल आबिद,दीपक चक्रवर्ती ,रीना त्रिपाठी आदि मुख्य रूप में उपस्थित रहे।

महाधिवेशन में प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में अभियन्ताओं ने प्रतिभाग किया।

मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था के जटिल मामले में अविकसित भ्रूण को अलग कर शान्या स्कैन्स एंड थेरानास्टिक्स के डाक्टरों ने स्वस्थ बच्चे का जन्म बनाया संभव

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स, लखनऊ के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करते हुए जटिल जुड़वा गर्भावस्था की समस्या का समाधान लेजर तकनीक का उपयोग करके किया है। डॉक्टरों ने 36 वर्षीय महिला के गर्भ में पल रहे मोनोकोरियोनिक जुड़वा बच्चों के भ्रूण में से अविकसित भ्रूण को लेजर तकनीक द्वारा अलग कर स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का मार्ग प्रशस्त किया। इस महिला का पूर्व में पांच बार गर्भपात हो चुका था। यह जटिल प्रक्रिया डॉ. प्रतिमा राधाकृष्णन, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, बेंगलुरु के कुशल मार्गदर्शन में डॉ. अदिति अग्रवाल, निदेशक भ्रूण चिकित्सा, शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स द्वारा पूरी की गई। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाली डॉ. अदिति अग्रवाल, डायरेक्टर फीटल मेडिसिन, शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स, लखनऊ ने बताया, दुर्भाग्य से, महिला के गर्भ में विकसित हो रहे जुड़वा भ्रूण में से एक भ्रूण बिना सिर के विकसित हो रहा था, इस स्थिति को मेडिकल साइंस में अक्रीनिया कहते हैं। उन्होंने बताया, ष्इस जटिल स्थिति का समाधान करने के लिए, हमने लेजर तकनीक का उपयोग करके असामान्य भ्रूण को अलग करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में, लेजर बीम का उपयोग करके अविकसित भ्रूण को रक्त आपूर्ति करने वाली नसों को बंद कर दिया गया। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और सटीकता के साथ करनी होती है, यह एक दुर्लभ मामला था। डॉ. प्रतिमा राधाकृष्णन ने कहा, मोनोकॉरियोनिक जुड़वां एक ही प्लेसेंटा को साझा करते हैं और इस कारण से कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। ये संरचनात्मक रूप से सामान्य भ्रूण होते हैं। फीटोस्कोपिक लेजर और इंटरस्टिशियल लेजर इन जटिलताओं को हल करने में मदद कर सकते हैं और एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। हर भ्रूण का जीने का अधिकार होता है और उन्हें निश्चित रूप से एक मौका दिया जाना चाहिए। सफलतापूर्वक प्रक्रिया के बाद, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मां ने गर्भधारण के 35वें सप्ताह में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जो अब पूरी तरह से ठीक है। यह प्रक्रिया इस क्षेत्र में पहली बार सफलतापूर्वक की गई है, और यह शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स के डॉक्टरों की विशेषज्ञता और जटिल गर्भावस्थाओं के इलाज में उनकी क्षमता का प्रमाण है। यहाँ फेटोस्कोपिक लेजर द्वारा मोनोकोरियोनिक जुड़वा बच्चों में होने वाली गंभीर जटिलताओं का इलाज संभव है। खासतौर से जटिल मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था की समस्या से जूझ रही महिलाओं के लिए शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स द्वारा उपलब्ध कराया गया यह इलाज एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स के एमडी एंड सीईओ डॉ. नर्वेश कुमार ने कहा, मोनोकोरियोनिक जैसी जटिल गर्भावस्था की समस्याओं का इलाज अब शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स पर उपलब्ध है। वर्तमान में शान्या स्कैन्स एंड थेरानॉस्टिक्स फीटल मेडिसिन, न्यूक्लीयर मेडिसिन, डायग्नोस्टिक एवम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एवम थेरानॉस्टिक्स के क्षेत्र में निरंतर प्रदेश की जनता को ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

पंचकोषात्मक पद्धति के जरिए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। हरदोई जनपद के पं बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अल्लीपुर में विद्याभारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण दिवस के सप्तम दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तरप्रदेश हेमचंद उपस्थित रहे। जनपद के पं बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अल्लीपुर में गुरुवार को विद्याभारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण दिवस के सप्तम दिवस पर मुख्य अतिथियों का नवीन आचार्या वहनों के द्वारा मुख्य अतिथियों का तिलक बंधन लगाकर स्वागत किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्जवलन व पुष्पार्चन किया गया तथा वंदना का कार्यक्रम हुआ। मंच संचालन श्रावस्ती संभाग कैलाश वर्मा के द्वारा किया गया तथा आये हुए मुख्य अतिथियों का परिचय प्रदेश निरीक्षक मिथिलेश अवस्थी के द्वारा किया गया। वंदना कार्यक्रम के पश्चात क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तरप्रदेश हेमचंद का स्वागत सह मंत्री जन शिक्षा समिति कौशल किशोर वर्मा ने किया। संस्कृति बोध परियोजना प्रमुख राजकुमार का स्वागत लखनऊ संभाग के संभाग निरीक्षक श्याममनोहर शुक्ल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तरप्रदेश हेमचंद ने सर्वांगीण समग्र विकास की कल्पना पर विस्तृत प्रकाश डाला और कहा पंचकोषात्मक पद्धति के जरिए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। चतुर्थ सत्र श्रावस्ती संभाग कैलाश वर्मा के द्वारा प्रश्न पत्र निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई। शारीरिक का सत्र हुआ जो जिसमे मुख्य शिक्षक प्रांतीय शारीरिक प्रमुख के द्वारा ओम प्रकाश के द्वारा विधिवत शिक्षण कार्य हुआ। इस मौके पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा विद्या भारती शीर्षेन्दुशील त्रिवेदी विपिन, सीतापुर संभाग निरीक्षक रणवीर सिंह, लखनऊ संभाग श्याममनोहर शुक्ल, साकेत संभाग मिथिलेश सिंह, व्यवस्था के आचार्य तथा नवीन आचार्य प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे।

उ0प्र0 प्रधानाचार्य परिषद के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विचार गोष्ठी आयोजित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के तत्वाधान में लखनऊ स्थित पी डब्लू डी डिप्लोमा कर्मचारी संघ के सभागार में आज को माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ० हरेंद्र कुमार राय एवं संचालन प्रदेशीय महामंत्री डॉ० सुखपाल सिंह तोमर ने की। गोष्ठी में प्रधानाचार्यों की मांगों के संबंध में महामंत्री ने विस्तृत चर्चा करते हुए प्रतिनिधियों का सुझाव आमंत्रित किया। गोष्ठी के प्रारंभ में सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन शिक्षा निदेशक डॉ० महेंद्र देव,अध्यक्ष डॉ० हरेंद्र कुमार राय, संरक्षक देव कृष्ण शर्मा, डॉ० वीरेंद्र प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा आयोजक डॉ० महेंद्र नाथ राय ने किया। महामंत्री ने मांगों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन सर्वश्री प्रवीण जी सहारनपुर, विपिन सिंह आगरा, मनजीत सिंह, डॉ०दिनेश शर्मा अलीगढ़ ,श्री वेद प्रकाश सुल्तानपुर, प्रदीप गुप्ता, अनिल जालौन आदि ने समर्थन करते हुए परिषद की एकता पर जोर दिया। शिक्षा निदेशक ने अपने संबोधन में परिषद को आश्वस्त किया कि आपकी मांगे जायज है और हमने आपकी मांगों के संबंध में शासन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का प्रस्ताव पूर्व में कर चुके हैं। आगामी जुलाई माह में शासन के स्तर से लंबित आदेशों को निर्गत कराने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष, महामंत्री तथा संरक्षक द्वय ने शिक्षा निदेशक को स्मृति चिन्ह देखकर सम्मानित किया। द्वितीय सत्र में मांग पत्र को लेकर अनेकानेक प्रधानाचार्यों ने अपना विचार रखा। संरक्षक देव कृष्ण शर्मा ने सबकी उपस्थिति के लिए आभार एवं धन्यवाद दिया। संयोजक डॉक्टर महेंद्र नाथ राय ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए परिषद हित में कार्य करने की प्रेरणा दी।

जेके कॉटन मिल की जमीन पर बनेगा 150 कमरों का ताज होटल

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में होटल उद्योग में नई शुरुआत होने जा रही है। देश की सबसे बड़ी आतिथ्य कंपनी ताज कालपी रोड पर स्थित जेके कॉटन मिल की जमीन पर 150 कमरों का होटल बनाने जा रही है। फाइव स्टार इस होटल के लिए जेके अर्बनस्केप्स और ताज की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के बीच अनुबंध हुआ है। इसके साथ ही जमीन के नक्शे का प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। यह होटल एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। दिल्ली में हुए समझौते के दौरान आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत छतवाल ने कहा कि देश के स्मार्ट शहरों में कानपुर का शामिल होना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की प्रगति आतिथ्य परिदृश्य को बढ़ावा दे रही है। इस होटल के लिए जेके अर्बनस्केप्स के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। इस होटल में पूरे दिन भोजन, दो विशेष रेस्टोरेंट और वेलनेस सर्किल स्पा की सुविधा होगी। इसके अलावा 10 हजार वर्ग फीट से अधिक जगह भोज स्थल के लिए आरक्षित रहेगी। वहीं जेके अर्बनस्केप्स डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन अभिषेक सिंहानिया ने कहा कानपुर में प्रतिष्ठित ताज ब्रांड लाने के लिए आईएचसीएल के साथ साझेदारी से वे बहुत उत्साहित हैं।

आईएचसीएल के उत्तर प्रदेश में 26 होटल हो जाएंगे

यह होटल शहर के परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। इस होटल के साथ ही आईएचसीएल के उत्तर प्रदेश में 26 होटल हो जाएंगे। इनमें से 13 निर्माणाधीन हैं। जेके अर्बनस्केप्स डेवलपर्स लिमिटेड जेके सिंहानिया परिवार के बड़े व्यवसाय का हिस्सा है। इसे पहले जेके कॉटन लिमिटेड नाम से जाना जाता था। अक्तूबर 1924 में एक इसे निजी इकाई के रूप में शामिल किया गया था।

बाइक सवार दंपती को ट्रक ने मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

हमीरपुर, संवाददाता। हमीरपुर जिले में जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव के बेतवा पुल के पास ट्रक चालक ने बाइक सवार दंपती को पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति सामान्य की। घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। जालौन जनपद के आटा थाना क्षेत्र कहटा गांव निवासी रमाकांत उर्फ लल्ला राजपूत (38) पुत्र रामभरत व उनकी पत्नी गीता देवी (35) के साथ बाइक से हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव स्थित अपनी ससुराल में जा रहे थे।

ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर

जैसे ही जरिया थाना के चंडौत डांडा गांव के पास बेतवा पुल पार कर कुछ दूर पहुंचे। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक ट्रक के नीचे आ गई। रमाकांत ट्रक के टायर के नीचे आकर कुचल गए।

चालक मौके से फरार

इससे रमाकांत की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में पत्नी गीता देवी के पैर ट्रक के नीचे आने से बुरी तरह घायल हो गई । पुलिस ने एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल गीता को उरई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी भेजा।

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है, लेकिन मौका देख ट्रक चालक फरार हो गया।

संक्षिप्त खबरें

नाबालिग बेटी को बनाया ह्वस का शिकार

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पिता पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप है। मां ने भी साथ दिया। दोनों आरोपी फरार हैं। मामले में चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना खंदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां 14 वर्षीय किशोरी ने पिता पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मां पर भी पिता का साथ देने का आरोप है। यही नहीं चाचा और दादी के विरोध जताने पर उनकी पिटाई भी कर दी। मामले में पुलिस ने चाचा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी पिता और मां घर से फरार हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई

बांदा, संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र के किलेदार पुरवा में सोमवार रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अलीगंज पोड़ाबाग निवासी अनिल राजपूत (26) पुत्र मल्लू राजपूत मकानों में पुताई और पेंटिंग का काम करता था। सोमवार रात को वह किसी काम से बाइक लेकर किलेदार पुरवा की तरफ गया था। वहां पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार अनिल छिटककर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी पर दादा का लड़का छोटू मौके पर पहुंचा और किसी तरह उसे जिला अस्पताल लाया, वहां पर चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा कालका निवासी फूटा कुआं पल्हरी ने बताया कि मृतक अपने पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता भी की कई वर्ष पहे मृत्यु हो चुकी है। उसकी दो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। हादसे में अनिल की मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है।

पत्नी की जान गई, पति की हालत गंभीर

बांदा, संवाददाता। मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, पति की हालत गंभीर बनी हुई है। सोमवार को आपसी कहासुनी के बाद दोनों ने जान देने की कोशिश की थी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सतन्याव गांव निवासी पूजा (20) का उसके पति कृष्णकुमार (21) से सोमवार को सुबह किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर पूजा ने जहर खा लिया। पत्नी की हालत बिगड़ती देखकर पति छत पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा दी। इससे वह गंभीर घायल हो गया। परिजन दंपती को लेकर सीएचसी बबेरू आए। वहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से पूजा की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। बबेरू कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह का कहना है कि पति–पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ था। इसी के चलते दोनों ने खुदकुशी का प्रयास किया। मृतका के एक पुत्र है।

पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़, दो को लगी गोली, तीन गिरफ्तार

उरई, संवाददाता। उरई में एसपी डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर जिले के अंतर्राज्यीयध्अंतर्जनपदीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार देर रात को एसओजीध सर्विलांस टीम व थाना रेंढर पुलिस की सयुंक्त टीम द्वारा कमसेरा चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर व आने–जाने वाले लोगों ने बताया कि कुछ बदमाश कमसेरा अमखेड़ा रोड पर राहगीरों से लूट पाट आदि कर रहे है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई, तो बाइक सवार अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास किया गया। साथ ही, पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें टीम बाल–बाल बची और फिर पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें दो शातिर अभियुक्त सुनील कुमार कुशवाह निवासी ग्राम बघावली थाना रामपुरा, अखिलेश पांचाल निवासी मोहल्ला भवानीराम कस्बा जालौन पैर में गोली लगने से घायल हुए।

ये सामान हुआ है बरामद

वहीं, पंकज सिंह राजावत निवासी ग्राम बिरिया थाना माधोगढ़ ने सरेंडर कर दिया। इन सभी के पास से तीन तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और बाइक बरामद हुई हैं। घायल बदमाशों सुनील कुशवाहा और अखिलेश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।

नवनिर्वाचित युवा सांसद इकरा हसन ने ली शपथ

शामली, कैराना, संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 18वीं लोकसभा के लिए जनता द्वारा चुनकर आईं नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने संसद भवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 18वीं लोकसभा के लिए जनता द्वारा चुनकर आईं कैराना लोकसभा की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन दो दिन पहले संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गईं थीं।

आठ वर्षों में 900 हेक्टेयर बढ़ी आम की बागवानी

सहारनपुर, संवाददाता। जनपद के किसानों को आम की बागवानी खूब भा रही है। इसके चलते पिछले आठ वर्षों में जिले में आम के क्षेत्रफल में 900 हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। अब आम का रकबा बढ़कर 26500 हेक्टेयर हो गया है। जनपद आम की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। यहां की बेहट फल पट्टी के साथ ही कई अन्य विकास खंडों में आम की अधिक बागवानी है। इनमें मुजफ्फराबाद, साढौली कदीम, नकुड़, गंगोह, रामपुर मनिहारान, नानौता और सरसावा प्रमुख हैं। यहां दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, गुलाब जामुन, मल्लिका, आम्रपाली, कलमी मालदा आदि प्रजातियों के बाग बहुतायत में हैं। अच्छे उत्पादन और बाजार में मांग के चलते किसान बाग का रकबा बढ़ा रहे हैं। आम के अलावा जनपद में पिछले आठ वर्षों में अमरूद का रकबा 190 और लीची 270 हेक्टेयर बढ़ी है। हालांकि इस अवधि में आम के कुछ अनउत्पादक बाग पुराने होने की वजह से कटे भी हैं। इसके बावजूद जिले में आम की बागवानी बढ़ रही है। जनपद में साढौली कदीम विकास खंड के 16 गांवों को आम की फल पट्टी घोषित किया हुआ है।

मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर की चीन में मौत

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी मर्चेंट नेवी के इंजीनियर अनिल कुमार की चीन में मौत हो गई। मौत के बाद 80 वर्षीय मां रामकिशोरी श्रीवास्तव का रो–रोकर बुरा हाल है। बच्चे पिता के वापस आने की राह तक रहे हैं। शिक्षिका पत्नी अंजुलता तीनों को अकेले संभाल रही हैं। दुख के साथ परिवार को देखने की जिम्मेदारी भी उन पर ही है। आंसुओं को थामकर पति के पार्थिव शरीर को घर लाने के प्रयास में लगी हैं। पूरे दिन लॅपटाप पर बैठकर ईमेल से अधिकारियों से गुहार लगाती रहती हैं। वह यही कह रही हैं कि अब मैं हार गई हूं, पति के अंतिम दर्शन तो करा दो सरकार...। उनकी मदद करने के लिए चीन में निवास कर रहीं भारतीय नम्रता उपाध्याय ने चीन के अधिकारियों और भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। वह भी लगातार भागदौड़ में लगी हुई हैं। आगरा के अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। विदेश मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाया है। अंजुलता ने बताया कि पति के आखिरी बार दर्शन के लिए प्रयासरत हैं। मगर, कहीं से कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही। वह क्या करें समझ नहीं आ रहा। पूरे दिन इस उम्मीद में ईमेल करती हैं कि कोई मदद कर देगा। पति के शरीर को वापस ले आएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से विनती करते हुए कहा कि वह और उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। उन पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सास को संभालना बहुत मुश्किल है। 13 दिन होने पर भी कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके पति के पार्थिव शरीर को आगरा भिजवाने का प्रबंध करे।

क्या कर रहा दूतावास?

अंजुलता पति की कंपनी के अधिकारियों के भी संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी पार्थिव देह को शीघ्र लाने के प्रयासों में लगी है, लेकिन चीन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं। उनका कहना है कि वापसी की पूरी प्रक्रिया में 25 से 30 दिन लग सकते हैं। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे तो कुछ ही दिन में पार्थिव शरीर वापस लाया जा सकता है।

नम्रता उपाध्याय कर रहीं मदद

अंजुलता ने बताया कि मंगलवर को चीन में रह रही भारतीय नम्रता उपाध्याय ने संपर्क किया। बताया कि वह दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने दुःख व्यक्त किया कि एक आमजन को सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है, यदि कोई नेता होता तो परवाह की जाती। नम्रता संबंधित विभागों से बात कर चुकी हैं, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे रहा है।

दुष्कर्म के आरोपी की मौत, पीटने के आरोपियों के घर हंगामा

शामली, संवाददाता। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ने मेरठ के अस्पताल में मंगलवार को दम तोड़ दिया। पांच दिन पहले ही दुष्कर्म के आरोपी को कुछ लोगों ने अपहरण कर पीटा था। मृतक युवक के गुस्साए परिजन शव को मेरठ से लेकर सीधे आरोपियों के घर पहुंचे और खूब हंगामा किया। पुलिस से भी परिजनों की खूब नोकझोंक हुई। बाद में कार्रवाई के आश्वासन पर ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल, लपराना गांव के सावन (22) पर एक किशोरी को बहला–फुसाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। आरोपी जमानत पर छूट गया था। 20 जून को वह बनत के निकट शामली तहसील में गुंडा अधिनियम के मामले में तारीख पर गया था। आरोप है कि वहां से लौटते समय युवक का अपहरण कर लिया गया था और बंधक बनाकर पूरी रात पिटाई की थी। दूसरे दिन सुबह उसे घर के बाहर गंभीर हालत में फेंक दिया था। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया था। युवक का मेरठ मेडिकल में उपचार चल रहा था। युवक पक्ष की तहरीर पर 11 के खिलाफ शामली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार की देर शाम करीब छह बजे सावन ने मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजन सावन के शव को लेकर सीधे आरोपियों के घर के बाहर पहुंचे और शव को रखकर खूब हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साढ़े सात से लेकर रात नौ बजे तक परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया मगर वह नहीं माने। पुलिस से भी नोकझोंक हुई। मामले में हत्या की धारा की बढ़ोत्तरी की भी मांग की गई। बाद में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के आश्वासन पर परिजन शांत हुए और गांव के श्मशान घाट पर ही शव का अंतिम संस्कार किया गया है। एसपी अभिषेक का कहना है कि युवक पर हमले के आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

युवकों ने सेल्समैनों को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में अनवरगंज स्टेशन मोड़ के पास सोमवार देर रात दुकान खोलकर शराब न देने पर युवकों ने सेल्समैनों को जीटी रोड पर दौड़कर पीटा। दोनों सेल्समैनों को लहूलुहान देख लोग जुटे, तो हमलावर भाग गए। रायपुरवा थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद चार हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। कोहना क्षेत्र में रहने वाली मंजुल कनौडिया के नाम से अनवरगंज स्टेशन मोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान है। सोमवार रात लगभग साढ़े 11 बजे शराब की दुकान पर तीन युवक स्कूटी पहुंचे और सेल्समैन संचित और घनश्याम पाल से दुकान खोलकर शराब देने को कहा। चूंकि दुकानें सिर्फ दस बजे तक ही दुकान खोलने और शराब बिक्री की अनुमति है इसलिए उन्होंने इन्कार कर दिया। इस युवक भड़क गए और दुकान का शटर पीटने लगे। दोनों सेल्समैन उन्हें समझाने के लिए बाहर आए तो युवकों ने साथियों को बुलाकर दोनों पर हमला कर दिया। लाठी–डंडे, सरिया, पत्थरों व वाइपर से जीटी रोड पर दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग जुटने शुरू हुए तो हमलावर भाग गए।

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले में हत्या का प्रयास, बलवा, गाली, धमकी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मंगलवार को लक्ष्मीपुरवा निवासी अजय उर्फ आशीष, लकी उर्फ शरद, सोहित वर्मा और जय वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पिता ने डांटा तो बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर दी जान

मेरठ, संवाददाता। मेरठ से सटे बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव रामराज में मंगलवार रात साढ़े नौ बजे मोबाइल चलाने से डांटने पर दसवीं के छात्र अंगद (14) ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। छात्र की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने परिवार और पिता पर प्यार न करने की बात लिखी है। गांव रामराज के मोहल्ला माया नगर में नितिन चौधरी का परिवार रहता है। उनका चौधरी ट्रांसपोर्ट नाम से कारोबार है। मंगलवार रात नितिन का बड़ा बेटा अंगद कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वह मोबाइल भी चला रहा था। पिता ने उसे डांट दिया और अधिक मोबाइल न चलाने के लिए कहा। इसी बात से नाराज होकर अंगद ने पिता की रिवॉल्वर से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे की तरफ दौड़े। अंगद को खून से लथपथ देखकर उनके होश उड़ गए। उसे मेरठ के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी देहात कमलेश बहादुर सिंह ने बताया कि छात्र की जेब से सुसाइड नोट मिला है, इसमें उसने पिता पर बाइक और मोबाइल न दिलाने की बात लिखी है। बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव रामराज में खुदकुशी करने वाले दसवीं के छात्र अंगद ने मौत से पहले सुसाइड नोट लिखा है। उसने लिखा है कि उसके पिता ने बाइक मोडिफाइड कराई। नई बाइक नहीं दिलवाई। नया मोबाइल नहीं दिलवाया। इसके चलते मैं जीना नहीं चाहता। इसी से तंग आकर वह आत्महत्या कर रहा है। मृतक अंगद के मुताबिक जब अपने दोस्तों पर नए मोबाइल देखता तो उसके मन में भी नए मोबाइल की चाहत बढ़ जाती थी। वह दिल ही दिल में अपने अरमानों को घोट लेता था। पिता द्वारा फटकार लगाई जाने से खिन्न होकर शायद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। पढ़ाई में कमजोर होना उसके लिए अभिशाप बन गया था। पिता उसे हर समय पढ़ाई के लिए फटकार लगाते थे। शायद उसकी आत्महत्या का यही मुख्य वजह रही होगी। परिजन कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि घर वालों का दबाव था, इसलिए आत्महत्या की।

मां और भाई का रो–रोकर बुरा हाल

छात्र अंगद के पिता नितिन चौधरी ट्रांसपोर्टर हैं। उसके अपने 8 ट्रॉले शुगर फैक्टरी में संचालित होते हैं। अंगद का एक छोटा भाई 8 वर्ष का है। अंगद की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। मृतक अंगद के एक छोटा भाई रुद्र व उसकी माता पूजा का रो रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोग पहुंचते रहे।

किशोरों की सहनशक्ति हो रही कम

मनोचिकित्सकों का कहना है कि आजकल टीवी–फिल्मों के प्रभाव और फास्ट फूड खाने से किशोरों में सहनशक्ति कम हो रही है, जिसके कई बार नतीजे गंभीर भी हो जाते हैं। जैसा कि रामराज क्षेत्र में हुई घटना में हुआ। जिला अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेंद्र किशोर ने बताया कि इस तरह की भावना के कई कारण हैं। सबसे आम है निराशा। जब बच्चे, किशोर या युवा को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह कई बार गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। ऐसे में पेशेवर से मदद लेनी चाहिए। मनोचिकित्सक डॉ. रवि राणा ने बताया कि अगर किशोर गुस्सैल है तो उसे बताएं कि समस्या वह नहीं है, बल्कि उसका गुस्सा है। अगर परिजनों को लगे कि उसके गुस्से या आक्रमकता के लिए किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है तो जरूर संपर्क करें। परिजन बच्चों के साथ वक्त बिताएं।

मेडिकल कालेज में सीटी स्कैन शुरू

सहारनपुर, संवाददाता। राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने वर्चुअल सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। भर्ती मरीजों के रोजाना सीटी स्कैन होंगे, जबकि ओपीडी में आने वाले मरीजों को तारीख मिलेगी। टेक्नीशियन की कमी के चलते ओपीडी मरीजों के प्रतिदिन सीटी स्कैन संभव नहीं है। मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के काउंसिलिंग हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें लखनऊ स्थित स्वास्थ्य महानिदेशालय में प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक द्वारा किए गए सीटी स्कैन मशीनों के वर्चुअल उद्घाटन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। उद्घाटन के दौरान उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई जा रही योजनाओं विशेषकर चिकित्सा योजनाओं एवं सुविधाओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए सीटी स्कैन जैसी महंगी तथा आधुनिकतम मशीनों को मेडिकल कॉलेजों में स्थापित कराकर जनता को सीधे लाभ पहुंचने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके बाद वर्चुअल सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, नकुड़ विधायक के भाई विकेश चौधरी, प्राचार्य डॉ. सुधीर राठी, डॉ. गगन गर्ग, डॉ वीरेंद्र सिंह, डॉ नवाब सिंह आदि मौजूद रहे।

रोजाना 20 सीटी स्कैन होंगे

मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोस्टिक डॉ. प्रत्युष ने बताया कि यह सीटी स्कैन मशीन अत्याधुनिक है, जिससे अभी रोजाना 20 सीटी स्कैन किए जाएंगे। जिनकी क्षमता भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। सीटी स्कैन होने के उपरांत रिपोर्ट भी दो दिन के भीतर मरीज को दे दी जाएगी। उद्घाटन के दिन सबसे पहला सीटी स्कैन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में भर्ती ग्राम पटनी निवासी 56 वर्षीय रेनू सैनी का किया गया। मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन शुरू हो गए हैं। टेक्नीशियन की कमी है, इसलिए अभी भर्ती मरीजों के ही सीटी स्कैन किए जाएंगे। जो मरीज ओपीडी में आएगा, उन्हें तारीख दी जाएगी।

रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चक्कर काटते रहे परिजन

शामली, संवाददाता। दुष्कर्म के आरोपी सावन का अपहरण करने के बाद मारपीट के मामले में पुलिस ने दो दिन तक परिजनों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की थी। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर खूब आरोप लगाते हुए हंगामा कियाा। आरोप है कि दो दिन बाद 22 जून को मामले की 11 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके भाई को झूठा फंसाया गया था। उसका कोई लेना देना नहीं था। अब उसका भाई मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जमानत पर आने के बाद 20 जून को कोर्ट से लौटते समय आरोपियों ने उसके भाई का अपहरण कर उसे खूब पीटा था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।